जो उसे 1993-94 के गरीबी अनुपात के आधार पर प्राप्त हो गया होता।

(ग) जी। नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरण आपूर्ति में विलम्ब

*29. **श्री ईश दत्त यादव :**

चौधरी हरमोहन सिंह यादव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपूर्तिकर्त्ताओ द्वारा उपकरण आपूर्ति में विलम्ब करने के कारण कई विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ हैं,

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं में विलम्ब हुआ हैं या विलम्ब हो रहा हैं, और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हैं, यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई हैं ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (श्री पी0 आर0 कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उपस्कर की आपूर्ति से विलम्ब का एकमात्र जिम्मेदार आपूर्तिकर्त्ताओं को ही नहीं ठहराया जा सकता हैं । सरकार सभी परियोजनाओं की गहन रूप से मानीटरिंग कर रही हैं तथा उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई कर रही हैं जिसमें निर्माताओं के साथ सम्पर्क करना तथा अन्य अवरोधों को दूर करना शामिल हैं। नौवीं योजना की जो परियोजनाएं उपस्कर की दे से आपूर्ति करने के कारण विलम्बित हुई हैं/हो रही हैं, वे निम्नलिखित हैं :-

(i) संजय गांधी टीपीपी (2 X 210 मे0 वा0)

(ii) बज-बज टीपीएस (2 x 250 में0 वा0)

(iii) मेजिया टीपीएस (3 x 210 मे0 वा0)

(iv) ब्रह्मपूरम डीजी सैट (5 x 20 मे0 वा0)

(v) कथालगुड़ी सीसीजीटी (2 x 33.5 मे0 वा0 + 3 x 30 मे0 वा0)

टिहरी बांध को पूरा किया जाना

*31. **श्री मनोहर कान्त ध्वानी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिहरी बांध को पूरा करने के लिए वर्ष 2002 तक की समय सीमा तय की हैं,

(ख) क्या यह सच हैं कि इस कार्य के लिए 25 प्रतिशत राशि का अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना था, यदि हां, तो क्या वह अपना वार्षिक अंशदान कर रही हैं,

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से अंशदान प्राप्त किए बिना भी केन्द सरकार ने इसे पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि जुटाने का प्रबंध कर लिया हैं, और

(घ) दिसम्बर, 1998 तक इस बांध पर कुल कितनी राशि खर्च हुई हैं और आगामी तीन वर्षों में अन्तिम रूप से कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना हैं ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-। को वर्ष 2002 तक पूरे किए जाने का कार्यक्रम हैं।

परियोजना को इस तरह से डिजाईन किया गया हैं कि यह सिंचाई के साथ-साथ विद्युत लाभ भी प्रदान करेगी। सिंचाई घटक की लागत पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं । तथापि, विद्युत घटक के बारे में,लगात की भागीदारी भारत सरकार और उ0 प्र0 सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में की जा रही हैं । कुल मिलाकर लागत की भागीदारी भारत सरकार और उ0 प्र0 सरकार के मध्य 60 : 40 के अनुपात में की जा रही हैं । 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार 718.66 करोड़ रुपये की देय राशि की तुलना में उ0 प्र0 सरकार ने 372.69 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

उ0 प्र0 सकार द्वारा निधियों को निर्मुक्त न किए जाने की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की गई हैं। उ0 प्र0 सरकार सिंचाई घटक के लिए अपनी वित्त पोषण की देयताओं की पूर्ति करने के लिए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अंतर्गत आंशिक वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे ताकि विद्युत घटक के संबंध